

GAGNEJA PROPERTIES
 CONTACT FOR SALE, PURCHASE RENT & LEASE
 ✓ Shops ✓ Houses
 ✓ Industrial Property
 ✓ Commercial Property
 ✓ Agriculture Land
 REAL ESTATE WITHOUT THE HASSLE
 MO.-8630672525, 8279444462
 ADD- SRA F69, Shop No.4, Adarsh Colony, Rudrapur

मलबे में दबने से चार की मौत

भारी बारिश के बाद देर रात फाटा गदेरा उफान पर

रुद्र प्रयाग (उद संवाददाता)। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग के फाटा में हादसा हो गया। गदरे में आए मलबे में दबने से चार मजदूरों की मौत हो गई। सभी लोग नेपाल के थे, शवों को डीडीआरएफ की टीम रुद्रप्रयाग लेकर गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकाारी नन्दन सिंह रजवार ने बताया कि देर रात करीब डेढ़ बजे अत्यधिक बारिश के कारण फाटा हेलीपैड के पास खाट गदरे के पास चार लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना



मिली थी। सूचना मिलते ही टीम घटना स्थल के लिए मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य किया। वहां

चार लोग मलबे में दबे दिखे जिन्हें तुरंत वहां से निकाला गया, लेकिन तब तक चारों की जान जा चुकी थी। मृतक लोगों में तुल बहादुर पुत्र हरका बहादुर ग्राम सीतलपुर पोस्ट बुरवा बाजार थाना बुरवा बाजार जिला चित्तौन आंचल नारायणी, पून नेपाली, किशना परिहार दीपक बुरा जिला दहले आंचल करनाली नेपाल शामिल है। संयुक्त रेस्क्यू टीम में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ व जिला पुलिस के जवान शामिल रहे।

आपदा प्रभावितों को मुआवजे के लिए धरने पर बैठे कांग्रेसी विधायक

गैरसैण (उद संवाददाता)। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में विधायकों के सवालों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में आई आपदा से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विधान सभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा कि प्रदेश में सरकार का आपदा प्रबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है। आपदा से कई लोगों की जानें गयी हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, लोगों के घर (शेष पृष्ठ सात पर)



घर में घुसकर परिजनों पर हमला

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। किच्छा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दरऊ में विगत रात्रि हथियार बंद कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर परिजनों पर जानलेवा हमलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। ग्राम दरऊ निवासी अशफाक पुत्र महबूब का कहना है कि 20 अगस्त को उसके ताऊ द्वारा एक



तहरीर चौकी आजाद नगर किच्छा में दी थी। जिसके सम्बन्ध में 21 अगस्त को पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ समय बाद वापिस चली गयी। उसके बाद शाम को वह अपने घर पर अपने परिवार के साथ मौजूद था। तभी ग्राम के ही निवासी कुछ लोग लाठी डंडो, चापड़ व तेज धारदार हथियारों से लैस होकर जबरन उसके घर में घुस आये और उसे, उसकी पत्नी रूबी, पुत्री नाजरा को बुरी तरह (शेष पृष्ठ सात पर)

विधानसभा में बोले बेहड़-जिले को जमकर लूटा जा रहा है

लगता ही नहीं उधमसिंहनगर में कानून नाम की कोई चीज है: बेहड़

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। गैरसैण में चल रहे विधानसभा सत्र के कल दूसरे दिन किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने उधमसिंहनगर जनपद की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा जोरशोर से उठाते हुये कप्तान की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया और बोले की लगता ही नहीं उधमसिंहनगर में कानून नाम की कोई व्यवस्था है। जिले को जमकर लूटा जा रहा है और हम इसे लुटवा रहे है। आम लोगों के साथ पुलिस आये दिन दुर्व्यवहार कर रही हैं। श्री बेहड़ ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन नियम 310 के तहत उधम



सिंह नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुये कहा कि क्षेत्र में बलात्कार, हत्या, डकैती की घटनायें बढ़ रही है मगर पुलिस का काम जमीनों पर कब्जा और छुड़ाने तक सीमित रह गया है। यदि किसी को जमीन कब्जानी है या फिर छुड़वानी है तो वह ही पुलिस के पास जाता है। विध

ानसभा में श्री बेहड़ ने बताया कि अभी कुछ समय पहले कप्तान और थानाध्यक्ष पंतनगर द्वारा बाहर से आये कुछ लोगों को दिनेशपुर में 15 एकड़ भूमि पर कब्जा कराया गया। यही नही गदरपुर में केलाखेड़ा में 17 एकड़ भूमि को लेकर दो पक्षों में मतभेद चल रहा था जिसे दोनों पक्षकारों ने सुलझा लिया गया और एक

सड़क हादसे में बाल बाल बचा कार सवार परिवार

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। नगर के नैनीताल मार्ग पर कार की टक्कर से ई

आवश्यकता है
 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में एकाउंट्स का कार्य करने हेतु युवक एवं युवतियों की। टेली की जानकारी आवश्यक।
 -संपर्क करें-
8433432291



रिक्षा सवार चार लोगों की मौत की घटना के एक दिन बाद ही नैनीताल मार्ग पर आज प्रातः परशुराम चौक पर हल्लानी की ओर से आ रही कार की सामने से जा रहे

से ओवर टेक करने के दौरान हुई भिड़ंत में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जबकि उसमें सवार एक ही परिवार के सभी लोग सकुशल बच गये। हालांकि

कार चालक को चोट लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही सीपीयू कर्मि तत्काल मौके पर पहुंच गये। घटना इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर के (शेष पृष्ठ सात पर)

ट्रक के नो एंट्री में आने से उठे सवाल

रुद्रपुर। विशाल मेगामार्ट के सामने परशुराम चौक पर कार व ट्रक के मध्य हुई टक्कर में हांलांकि कार सवार सभी लोग सकुशल बच गये परंतु नो इंट्री होने के बाद भी शहर में ट्रक के प्रवेश होने से यातायात व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि यदि नो इंट्री के चलते ट्रक ने शहर में प्रवेश नहीं किया होता तो यह दुर्घटना भी नहीं होती। उनका यह भी आरोप है कि निजी स्वार्थों के चलते शहर में नो इंट्री महज औपचारिकता बन कर रह गई है। शहर की सीमाओं पर पुलिसकर्मि तैनात होने के बावजूद भी शहर में भारी वाहन बेखौफ प्रवेश कर रहे हैं। जो पुलिस की कार्यप्रणाली की वास्तविकता को उजागर कर रहा है। सीपीयू का काम महज नो इंट्री में शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर उनका चालान करने तक ही सीमित होकर रह गया है। शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों को रोकने की जिम्मेवारी किस की है। नो इंट्री में शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों का चालान करने के साथ ही उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करना जरूरी हो गया है जो उस दौरान शहर की (शेष पृष्ठ सात पर)

बढ़ रही 'हादसों की रफतार', आखिर कब सबक लेगी पुलिस!

यातायात व्यवस्था के नाम पर पुलिस और सीपीयू चालान काटने तक सीमित, नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां

रुद्रपुर। जिला मुख्यालय और आस पास की सड़कों पर हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यातायात नियमों का उल्लंघन है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन हादसों से सबक नहीं ले रहा। यातायात व्यवस्था के नाम पर पुलिस और सीपीयू सिर्फ चालान काटने तक सीमित नजर आ रही है। जिसके चलते आये दिन सड़कों पर निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित नैनीताल हाईवे पर बेकाबू कार की टक्कर से गर्भवती

सिस्टम की लापरवाही से बढ़ रहे हादसे: गावा

रुद्रपुर। सड़कों पर बढ़ रहे हादसों पर समाजसेवी एवं भाजपा नेता सुशील गावा ने गहरी चिंता व्यक्त की है। नैनीताल रोड पर शुक्रवार सुबह हादसे के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे सुशील गावा ने हादसे में चोटिल हुए लोगों को सहारा दिया और हाईवे पर जाम को खुलवाने में मदद की। जब उन्होंने देखा कि नो एंट्री में कम से कम पांच ट्रक खड़े हैं तो वहां पूरे सिस्टम पर बरस पड़े। गाबा ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब सात बजे से नो एंट्री लागू है तो ट्रक नो एंट्री में कैसे आ गये। उन्होंने घटना के बीस मिनट बाद मौके पर सीपीयू के पहुंचने पर भी नाराजगी जताई कहा (शेष पृष्ठ सात पर)

काफी बढ़ गया है लेकिन यातायात व्यवस्था अभी तक पुराने ढर्रे पर चल रही है। चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें शोपीस बनी हुयी हैं, चौराहों पर अकसर जाम की स्थिति रहती है। चौराहों के साथ साथ मुख्य बाजार एवं गलियों में भी जाम से बुरा हाल है। इसके अलावा आवास विकास, ट्रांजिट कैम्प, इंदिरा कालोनी, गंगापुर रोड के मार्गों पर भी अकसर जाम से बुरा हाल हो जाता है। पुलिस इस जाम की समस्या से निपटने के साथ साथ पुलिस बढ़ते सड़क हादसों पर भी (शेष पृष्ठ सात पर)



मानसून सत्र में गैरों के साथ अपनों के सवाल से धिरी सरकार

विपक्ष ने सदन में विधानसभा सत्रों की अवधि सबसे कम होने का मुद्दा उठाया

गैरसैण (उद ब्यूरो)। गैरसैण में आयोजित हो रहे मानसून सत्र के पहले ही प्रश्नकाल में सरकार को भाजपा के ही विधायकों के ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ा। भाजपा विधायकों ने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता से संबंधित सवाल लगाए थे, हालांकि कार्यसूची में शामिल होने के बावजूद अधिकांश विधायकों के सवालों का नंबर सदन में नहीं आ पाया। दरअसल, गुरुवार के दिन मानसून सत्र का पहला प्रश्नकाल था। इस सत्र में महज दो दिन ही प्रश्नकाल होना है। सत्र के लिए कुल 500 के करीब सवाल आए हैं। कार्यसूची में विधानसभा सचिवालय की ओर से कुल 83 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न लिए गए थे। इसमें से अकेले 53 सवाल भाजपा के विधायकों के हैं। जो प्रश्नकाल के लिए स्वीकृत कुल सवालों का करीब 63 फीसदी हैं। जबकि प्रश्नकाल के लिए कांग्रेस विधायकों के प्रश्नों की संख्या कुल महज 15 थी जो कुल प्रश्नों का 18 फीसदी बनती है। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों की ओर से भी काफी सवाल लगाए गए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल कांग्रेस विधायकों की ओर से भी पूछे गए उन पर अनुपूरक सवाल भी ज्यादातर भाजपा विधायकों की ओर से पूछे गए। इससे कई बार विपक्ष के विध

सत्रों की अवधि का निरंतर कम होना दुर्भाग्यपूर्ण : आर्य

देहरादून (उद संवाददाता)। गैरसैण में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन में सत्र की अवधि कम होने का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने एक शोध रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश भर में उत्तराखंड विधानसभा की सबसे कम अवधि है। प्रदेश सरकार ने कहा, सदन को संचालित करने के लिए बिजनेस के आधार पर सत्र की अवधि तय की जाती है। मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में सत्र की अवधि को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया। विधानसभा सत्र में गुरुवार को प्रश्नकाल खत्म होते ही कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप सत्रों की अवधि तय नहीं की जा रही। एक संस्था के शोध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-2023 में देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के सत्रों की अवधि को मंत्रियों को उलझाने में मदद मिली। प्रश्न काल के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, सहदेव पुंडीर, बृजभूषण गैरोला ने सदन में अनुपूरक सवाल पूछे। विधानसभा



औसत अवधि 22 दिन रही, लेकिन उत्तराखंड तो इसमें भी न्यून स्तर पर है। राज्य विधानसभा वर्ष 2022 में आठ दिन, 2023 में 10 दिन और वर्ष 2024 में चार दिन चली। स्थिति यह है कि बजट भी एक ही दिन में पारित कर दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सत्रों की अवधि का निरंतर कम होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सदन में व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल में किसी स्पेशल विधानसभा के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर अनुपूरक सवाल भी उसी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी सत्र के लिए विधानसभा के पास 40 विभाग हैं। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आदर्श स्थिति यही है कि साल में विधानसभा के तीन उपवेशन हों, जिनकी अवधि 60 दिन हो। उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि बिजनेस के आधार पर तय की जाती है। सरकार की मंशा साफ है कि सदन की कार्यवाही चले। पीठ से विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने कहा कि वह भी चाहती हैं कि सत्रों की अवधि अधिक हो, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त बिजनेस हो। यदि अवधि कम भी हो तो देर तक सदन चलाया जा सकता है। सत्र कब आहूत करना है, इसकी अवधि कितनी होगी, यह सरकार तय करती है। फिर कार्यमंत्रणा समिति तय करती है और उसी के अनुरूप बिजनेस आता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सत्तापक्ष व विपक्ष, दोनों के सदस्यों को अपनी बात रखने को पर्याप्त समय देती हैं।

चौहान ने अनुपूरक सवाल उठाया लेकिन चालाकी से उसे पूरे राज्य से जुड़ा सवाल बना दिया, इस पर स्पीकर ने सदन में कहा कि विधायकों को मुन्ना चौहान से सवाल पूछने का तरीका सीखना चाहिए।

भ्रष्टाचार पर हो रहा है कड़ा प्रहार: अग्रवाल

गैरसैण। विधानसभा में नियम 58 पर विपक्ष के भ्रष्टाचार पर उठाए सवालों के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। अभी तक विजिलेंस ने रिश्वत लेने के मामले में 68 लोगों को ट्रैप कर जेल भेजा। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। कार्यभार संभालने के दिन से ही सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही सुनिश्चित कराई है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा कर आम जनता को राहत पहुंचाई है। देहरादून, नैनीताल में सतर्कता सेंटर का गठन करने के साथ ही पीडी, अल्मोड़ा में सब सेंटर भी स्थापित किए हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई को नैनीताल, देहरादून में विशेष जज नियुक्त है। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत को हेल्पलाइन नंबर 1064 जारी किया गया है। अभी तक 5971 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के सम्बन्ध में ट्रैप की कार्यवाही की गई है। ट्रैप की कुल 58 कार्यवाही में 10 राजपत्रित अधिकारियों और 58 अराजपत्रित कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है।

आज अगर अडानी डूबा तो देश डूब जाएगा : सुरेंद्र राजपूत

प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का केंद्र सरकार पर हमला

देहरादून (उद संवाददाता)। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामला देश का है। अगर हम गलत हों तो हमें सही कीजिए। अगर वो गलत हों तो हमारा साथ दीजिए। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेच दिया है। देश के तीन चार उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था हैं। आज वो दुनिया में नंबर एक बिजनेसमैन हैं। सब कह रहे हैं कि आज अगर अडानी डूबा तो देश डूब जाएगा। हमारे देश के पूंजीपति हमारे लिए काम करें, सरकार के लिए नहीं। हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में 142वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने परम मित्र की सारी कंपनी को क्यों बचा रही है। जब उन्हें ठेका देना होता है तो दूसरी कंपनी में केंद्रीय एजेंसी के छोड़े डालो, फिर वो कम्पनी ए। खरीद लेता है। ऐसे तमाम

मामले हैं। जहां छोपे पड़ते हैं, वो कंपनी ए। 1 ने खरीद ली। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके यहाँ पैसा लगाने को मजबूर किया जाता है। एसबीआई और एलआईसी से पैसा लगवाया गया। हम पूछना चाहते हैं कि अगर अडानी की कंपनी डूबी तो एलआईसी और एसबीआई के पैसे का जिम्मेदार कौन होगा। पैसा डूबा तो मेरा और आपका पैसा होगा। हमारी विदेश

नीति को दांव पर लगाया गया है। झारखंड में अडानी ने प्लांट लगाया, बिजली बांग्लादेश को बेच रहे हैं। सरकार ने 35 साल की लीज पर श्रीलंका के पोर्ट लिया, लेकिन अडानी को दे दिया। कोयले में मनी लाँड्रिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि 3.1 ट्रिलियन टन कोयले में खेल किया गया है। अडानी को जमीन केवल एक रुपये लीज पर दिया गया। एयरपोर्ट

सरकार बनाती है और 50 साल की लीज अडानी को दिए गए। देश का 57 फीसदी कार्गो अडानी पोर्ट पर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने सेबी के जरिए भी अडानी को बचाने का आरोप लगाया। कहा, इससे देश की प्रतिष्ठा खराब होती है। उन्होंने माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपति रहे, लेकिन कभी किसी को ये नहीं लगा कि सरकार का उनके प्रति कोई झुकाव है। यकीन यहां आप देख सकते हैं। आईआईटी को 120 करोड़ टैक्स का नोटिस जारी हुआ है, जबकि एक बाबा को पांच साल की जीएसटी माफ की गई है। जनता अब गले तक भर गई है। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो, इसलिए सरकार अभी चेत जाए।



पीड़िता की बिगड़ी तबीयत, रीक्रिएट होगा क्राइम सीन

नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी ड्राइवर-कंडक्टर बर्खास्त

देहरादून (उद संवाददाता)। अगस्त की रात आईएसबीटी परिसर में मुरादाबाद की किशोरी से गैंगरेप हुआ था। रोडवेज से अनुबंधित बस का ड्राइवर कश्मीरी गेट से किशोरी को

अपने साथ दून लेकर पहुंचा था। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बालिका निकेतन में तीन दिन किशोरी की

गैंगरेप से पहले मुरादाबाद में भी कई बार हुआ था किशोरी से दुष्कर्म

देहरादून। अंतरराज्यीय बस अड्डा (आइएसबीटी) देहरादून परिसर में परिवहन निगम की अनुबंधित बस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई किशोरी से उसके गृह क्षेत्र मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में भी दुष्कर्म हो चुका है। जांच में पुलिस को पता चला है कि किशोरी लंबे समय से यौन शोषण की शिकार होती आ रही है। किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में भी जानकारी दी है कि मुरादाबाद में भी उससे अलग-अलग समय पर अलग-अलग व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया है। इस आधार पर पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर ली है और इसे जांच के लिए मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया गया है। घटना के बाद से बालिका निकेतन में रह रही किशोरी की तबीयत गुरुवार शाम बिगड़ गई। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल कोरोनेशन में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा कि घटना के बाद से ही पीड़िता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। बालिका निकेतन में भी उसके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले की जांच देहरादून पुलिस यथावत करती रहेगी। पुलिस के अनुसार किशोरी ने बाल एवं महिला आयोग और बाद में पुलिस को दिए बयानों में उसके साथ पूर्व में दुष्कर्म होने की बात बताई है। इसके बाद पुलिस पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज करा चुकी है। बाल एवं महिला आयोग की ओर से पुलिस को मुरादाबाद में हुई दुष्कर्म की घटना के संबंध में अलग से मुकदमा दर्ज करने को कहा गया था।

पीड़िता के गृह जिले मुरादाबाद ट्रांसफर किया जाएगा। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने इसकी पुष्टि की। दुष्कर्म का यह घटनाक्रम गैंगरेप से पहले का है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने पहले भी दुष्कर्म होने का जिक्र किया। पूछने पर उसने एक व्यक्ति के बारे में बताया। लेकिन, जब आरोपी का नाम-पता पूछा गया तो पीड़िता ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। उत्तराखंड रोडवेज प्रबंधन ने बस में किशोरी के साथ गैंगरेप के आरोपी विशेष श्रेणी ड्राइवर-कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया है। बीते सप्ताह

आईएसबीटी परिसर में उत्तराखंड रोडवेज की बस में किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने पांच ड्राइवर और कंडक्टरों को गिरफ्तार किया था। रोडवेज की मंडलीय प्रबंधक (संचालन) पूजा केहरा ने बताया कि गुरुवार को विशेष श्रेणी कंडक्टर देवेन्द्र पाल और ड्राइवर राजपाल सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। जबकि, इससे पहले नियमित कंडक्टर राजेश सोनकर को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा अनुबंधित बस के ड्राइवर रवि कुमार और धमंदा कुमार की सेवाएं भी समाप्त की जा चुकी हैं।



से मंजूर हो गई है। लिहाजा, पुलिस अब दिल्ली से देहरादून तक गैंगरेप का क्राइम सीन दोहराएगी। पुलिस के अनुसार, 12

अपने साथ दून लेकर पहुंचा था। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बालिका निकेतन में तीन दिन किशोरी की

5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश



गैरसैन (उद संवाददाता)।

उत्तराखण्ड में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैन विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 5013.05 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। अनुपूरक में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बरसात के मौसम में आपदा से बेहाल क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों एवं पुनर्निर्माण कार्यों, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बजट पोटली खोल दी। वार्षिक बजट की भांति गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी यानी ज्ञान (जीवाइएएन) को अनुपूरक मांगों में भी प्राथमिकता मिली है। वाइब्रेंट विलेज यानी सीमांत गावों के विकास पर 130 करोड़ की बड़ी राशि खर्च की जाएगी। बड़े निर्माण कार्यों के लिए 748.40 करोड़ की राशि की व्यवस्था कर सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अवस्थापना विकास उसकी शीर्ष प्राथमिकता है। भराड़ीसैन में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम अनुपूरक मांगों प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि

सीमांत गावों के विकास पर खर्च होंगे 130 करोड़: राहत कार्यों एवं पुनर्निर्माण कार्यों, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल विश्वविद्यालय के लिए धनवर्षा

अनुपूरक बजट में राजस्व पक्ष में 3756.89 करोड़ और पूंजीगत पक्ष में 1256.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। केंद्रपोषित योजनाओं के लिए 1531.65 करोड़ और बाह्य सहायित योजनाओं के लिए 273.17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में जन कल्याण को समर्पित योजनाओं को अधिक बल मिला है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत एसडीआरएफ मद में 718.40 करोड़, एसडीएमएफ के अंतर्गत 218.60 करोड़, जिलाधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसरों के पुनर्निर्माण को 20 करोड़ की राशि दी गई है। अनुपूरक मांगों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत 698 करोड़ की राशि खर्च होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वृहद निर्माण कार्य सरकार की प्राथमिकता हैं। टिहरी झील के विकास को 50 करोड़, नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजना के

लिए 40 करोड़, गो सड़नों के निर्माण को 32 करोड़, राज्य संपत्ति विभाग के आवासीय और अनावासीय भवन निर्माण को 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

लिए 14 करोड़, पालीटेक्निकों के लिए भूमि की खरीद अथवा भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ की राशि और नर्सिंग कालेजों की स्थापना को 25 करोड़ रुपये

क धनराशि खर्च की जा सकेगी। नगरीय अवस्थापना के सुदृढीकरण और बाह्य सहायित योजनाओं के लिए 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आवास निर्माण को 96.76 करोड़, यूनिटी माल अथवा प्लाजा निर्माण को 69 करोड़, और सीवरेज प्रबंधन कार्यों के लिए एनजीटी के निर्देश पर रिंग फौंसिंग को 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण को 45.92 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन फेज-एक के लिए चार करोड़, उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि को एक करोड़, नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने को जमा धनराशि की वापसी को 50 लाख की राशि अनुपूरक मांगों में सम्मिलित की गई। **विभागवार किसको कितना**

बजट- धनराशि (हजार रुपये में)
विधानसभा- 36900, मंत्री परिषद- 32700, न्याय प्रशासन- 190560 निवार्चन-30600 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन- 9796751 वित्त, कर, नियो जन, सचिवालय अन्य सेवाएं-2071238 आबकारी-23000 पुलिस एवं जेल-1669399 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति-10037535 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण-4126296 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास-5713900 सूचना-2267000 कल्याण योजनाएं-2008837 श्रम और रोजगार-158666 कृषि कर्म एवं अनुसंधान-1101502 सहकारिता-325098 ग्राम्य विकास-2098295 सिंचाई एवं बाढ़-930204 उर्जा-1851025 लोक निर्माण कार्य-1640000 उद्योग-234537 परिवहन-481552 खाद्य-8150 पर्यटन-658652 वन-401759 पशुपालन संबंधी कार्य-527313 औद्योगिक विकास - 19264 अनुसूचित जातियों का कल्याण- 1097831 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- 5918881

सरकार की आय में हुई बढ़ोतरी: कैंग रिपोर्ट में पांच सालों में 6.71 फीसदी की औसत दर से बढ़ी प्रदेश की जीडीपी

देहरादून। उत्तराखण्ड में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच पांच वर्षों में 6.71 फीसदी की दर से बढ़ा है। हालांकि, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य पीछे है, लेकिन कोविडकाल की दुश्वारियों से उबरने के बाद प्रदेश में आर्थिक विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा है। यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैंग) की 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट से हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान मूल्यों पर 2018-19 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,30,314 करोड़ था। 2022-23 में यह 3,02,621 करोड़ हो गई। यानी राज्य में आर्थिक विकास 6.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर पर बढ़ा। राज्य का बजट आउट टर्न 10.59 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में 48,037 करोड़ से 2022-23 में 71,012 करोड़ हो गया। अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद उत्तराखण्ड से अधिक रही। 2018-19 से 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय जीडीपी 10.34 फीसदी की

औसत दर से बढ़ी। देश के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर कम रही। केवल वर्ष 2022-21 में उत्तराखण्ड वृद्धि दर अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही इस अवधि में राजस्व प्राप्तियां 14.00 प्रतिशत बढ़ गईं। 2021-22 में 15.82 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 16.22 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 15.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के अपने कर राजस्व में

20.65 प्रतिशत इजाफा हुआ। राज्य का कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है। 2021-22 में 11.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 46,810 करोड़ से बढ़कर 52,061 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 12.44 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व अधिशेष 4,128 करोड़ से बढ़कर 5,310 करोड़ हो गया, जो 2021-22 की तुलना में 28.63 प्रतिशत अधिक है, जबकि राजकोषीय घाट 2021-22 में 3,736 करोड़ से घटकर 2022-23 में 2,949 करोड़ हो गया, जो 21.07 प्रतिशत कम हो गया।

सदन में उत्तराखण्ड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक समेत आठ विधेयक भी हुए पेश

देहरादून। उत्तराखण्ड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को प्रदेश सरकार ने सदन पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं इसके साथ ही आठ विधेयक भी सदन पटल पर रखे गए। उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024। 2-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024। 3-उत्तराखण्ड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024। 4-उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा विधिवि संशोधन विधेयक 2024। 5-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक। 6-उत्तराखण्ड राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय विधेयक 2024। 7-उत्तराखण्ड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024। 8-विनियोग विधेयक 2024।

गुरु माँ एडवांस्ड डेन्टल क्लीनिक

WORLD-CLASS DENTAL CARE NOW IN YOUR CITY

रूट कैनाल विशेषज्ञ

डेन्टल इम्प्लांट

टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज

डॉ. ऑचल ढींगरा

बी.डी.एस., एम.डी.एस., एडवोकेट
रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक डेन्टीस्ट
सर्टिफाइड एस्थेटिक डेन्टीस्ट

Guru Maa Advanced Dental Care "A Multi Speciality Dental Clinic"

१ प्लॉट नं 1, सिविल लाइन्स, रुद्रपुर | ☎ 7452880018, 05944-245666

